of advances with balances of less than Rs. 25,000 for that year. For the year ended 31-3-93, banks were not required *to* classify such advances into performing and non-performing. Prudential norms on income recognition, assets classification and provisioning has been introduced from the accounting year beginning 1st April, 1992. As such data relating to 1991 and 1992 is not available.

(b) and (c) RBI have stated that they have no material to furnish as their present data maintainauce system docs not yield such information.

संसद सदस्यों द्वारा सीमा शुल्क विभाग से रिवाल्वरों/पिस्तौलों की खरीद

906. **श्री रामदेव भंडारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों द्वारा सीमा शुल्क विभाग से रिवाल्वर/पिस्तौल खरीदने के लिए लिख गए पत्रों में से किस महीने तक के पत्रों का निष्पादन किया जा चुका है ;

(ख) क्या मई-जून महीनों में लिख गये पत्रों का निष्पादन अभी तक नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण है तथा इनका निष्पादन कब तक कर दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) (क) सीमा-शुल्क विभाग से रिवाल्वरों/पिस्तौलों को खरीदने के लिए माननीय संसद द्वारा लिखे गये अप्रैल, 1994 तक के पत्रों का निपटान कर दिया गया है।

(ख) और (ग) अप्रैल, 1994 के बाद प्राप्त हुए पत्रों को लम्बित रखा गया था। आवंटन के लिए उपलब्ध हथियारों के स्टाक की समीक्षा करने के बाद, इन लम्बित पत्रों का अब निपटान किया जा रहा है।

Loans under the deferred credit Guarantee scheme

907. SHRI D1LIP SINGH JUDEV: Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state:

(a) what are the details of the loans disbursed during the last three years year-wise in each District in Madhya Pradesh by Industrial Development Bank of India for purchase of vehicles under the Deferred Credit Guarantee Scheme;

(b) how many vehicles were purchased by parties;

(c) how many among them were educated unemployed, and

(d) for how much time this Schemes is likely to continue ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) The details of assistance disbursed by the Industrial Development Bank of India (IDBI) under their Deferred Credit Guarantee Scheme namely; Bills Redisocounting Schemes (BRS) and Direct Discounting Scheme (DDS) for purhase of vehicles in Madhya Pradesh during the last three years are as under:

(Rs. crore)

	BRS	DDS	Total
1991-92	4.46	0.28	4.74
1992-93	8.94	0.10	9.04
1993-94	1.34	0.15	1.49